और करीब 32,000 लोगों को रोजगार देना निहित है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के वास्ते आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनेक विकासात्मक योजना स्कीमें तैयार की हैं। इन स्कीमों के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने/उनका उन्नयन करने के लिए राज्य सरकार के सगठनों, संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों, सहकारी समितियों, स्वैच्छिक एजेंसियों आदि को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस मंत्रालय की योजना स्कीमों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश स्थित फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की युनिटों को दी गई सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

फल और सब्जी संस्करण

	मध्य प्रदेश की दी गयी सहायता	45 लाख रु० की इक्विटी सहायता
1.	मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लि०, भोपाल (1990–91)	(बर्वई में फल और सब्जी प्रसंस्करण सयंत्र का सुदृढ़ करना)
2.	सतपुड़ा एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान (एस आई आर डी आई), भोपाल (1992–93)	2.585 लाख रु० की सहायता अनुदान (स्थान प्रयोगशाल के लिए)
3.	महिला चेतना मंच, भोपाल (1993–94)	5.90 लाख रु० का सहायता अनुदान (खुम्बी की खेती)
4.	मारफेड, भोपाल (1993–94)	72.00 लाख रु० का सहायता अनुदान (एन.सी.डी.सी. माध्यम से) (शीत–भंडारण की स्थापना के लिए)

फलों के उत्पादन में वृद्धि

1087 श्री राम जेठमलानी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन दशकों के दौरान देश में फलों के उत्पादन में 54.71 प्रतिशत तक वृद्धि हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 में फलों और सब्जियों का कितना-कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ग) देश में फलों और सब्जियों को कितनी मात्रा का उपभोग किये जाने का अनुमान है;

(घ) क्या सरकार ने फलों और सब्जियों की शेष मात्रा के प्रसस्करण हेतु उपयोग किए जाने हेतु देश में खाद्य प्रसस्करण उद्योग की क्षमता का आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त क्षमता कितनी है तथा क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा आवश्यक मात्रा के प्रसंस्करण किये जाने के बाद बची शेष मात्रा का उचित उपयोग करके उत्पादो को निरुत्साहित होने से बचाने के लिए उपाय कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण) उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) गत तीन दशकों में हुए फल और सब्जी के उत्पादन के कोई सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किंतु उपर्युक्त अवधि के दौरान उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि

हुई है। वर्ष 1993-94 के दौरान फल और सब्जियों का उत्पादन क्रमश: 25 मिलियन टन और 72 मिलियन टन होने का अनुमान है।

(ग) अनुमान है कि फल और सब्जियों की उपयोग मे लायी गयी कुल मात्रा में से 99 प्रतिशत की खपत देश में होती है और करीब 1 प्रतिशत का निर्यात किया जाता है।

(घ) से (च) 1-1-1994 की स्थिति के अनुसार फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की संस्थापित क्षमता 12.60 लाख टन होने का अनुमान है जो फलों और सब्जियों के मामले मे अनुमानित रूप से 25 20 लाख टन है।

Mismanagement in Private Nursing Homes

1088. SHRI KRISHAN LAL SHARMA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many private nursing homes in the country were allottted land on concessional rates and allowed to import costly and sophisticated medical equipments at reduced customs duty;

(b) whether it is also a fact that these private nursing homes do not treat patiants from poor and weaker sections of the socity of the country ;

(c) if so, the reasons therefor ;

(d) number of such instances which came up before the consumer protection council; and

(e) the decision of the council in this regard ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND) : (a) As 'Health' is a State subject, the State Governments allot land at concessional rates or otherwise to private nursing homes. However, Customs Duty Exemption Certificates have been issued by Directorate General of Health Services for import of medical equipments.

(b) and (c) Institutions who have availed of custom duty concessions are to be monitored by the concerned State Governments to ensure that free treatment according to the conditions of concessions allowed is given.

(d) and (e) Such information is not compiled.

Family Planning In Tribal Areas of Certain states

1089. SHRI NYODEK YONGGAM : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that family planning is a taboo to the tribals of Arunachal Pradesh, Bihar, Orissa, Rajasthan, Nagaland, Mizoram and Andhra Pradesh ;

(b) if so, what appropriate scheme has been formulated by the Central Government to remove such taboo ;

(c) whether there is any scheme to launch a special drive for implementation of family planning in the above States; and

(d) if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) 100% centrally sponsored Family Welfare schemes are under implementation in these states. The States have been requested to gear up their implementation.

Laproscopic Training Centres

1090. DR. NARREDDY THULASI REDDY : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) what are the names of laproscopic training centres which have been set up so far in the country;

(b) whether there is any proposal to set up more Laproscopic Training Centres; and

(c) if so, what are the deatils thereof ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKRANAND) : (a) The names of the existing 22 Central Leproscopic Centres located in different parts of the country are gaven in the enclosed statement (*See* below).